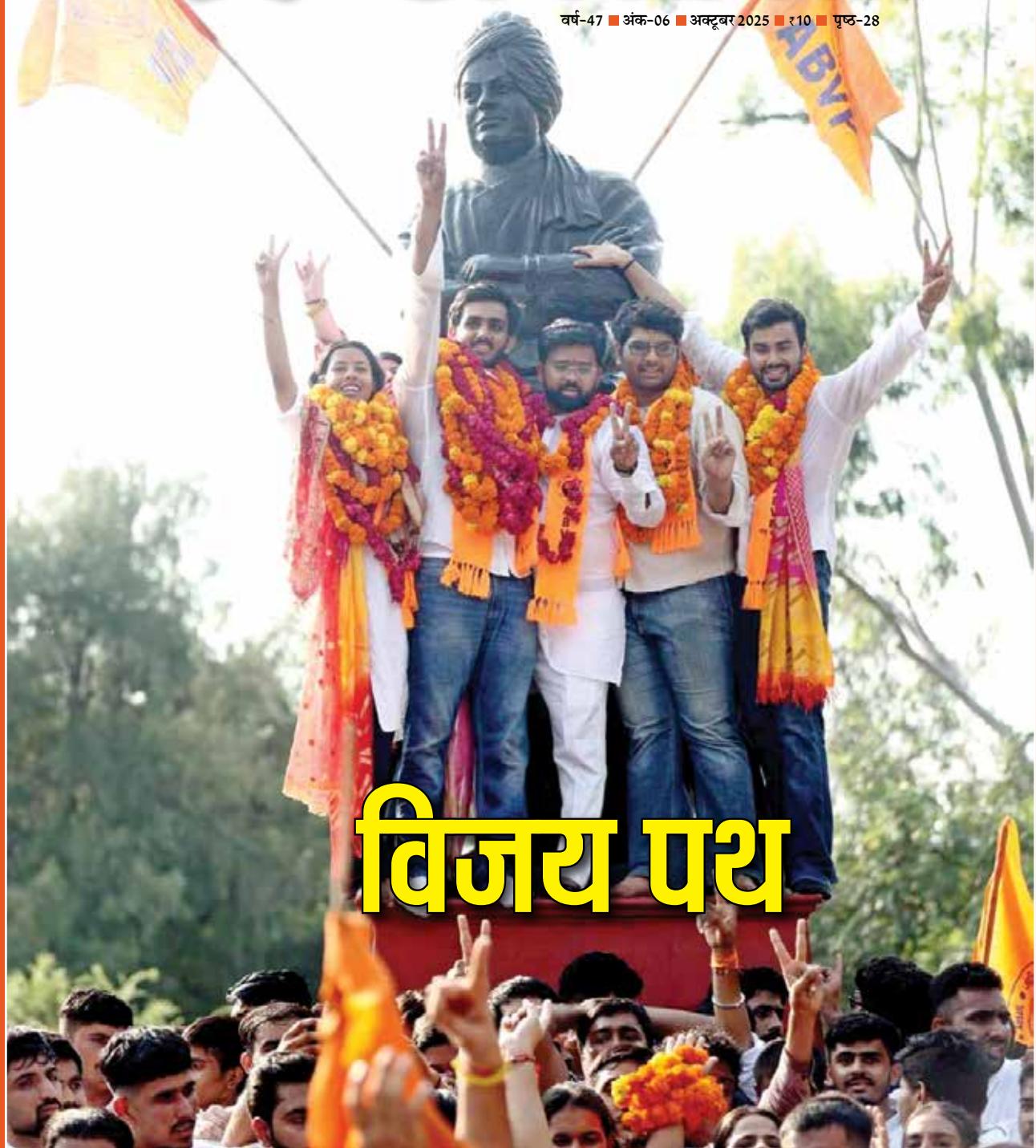




युवा छात्रशक्ति

वर्ष-47 ■ अंक-06 ■ अक्टूबर 2025 ■ ₹10 ■ पृष्ठ-28

विजय पथ





अहिल्यानगर : मोडिविजन राष्ट्रीय सम्मेलन के शुभारंभ के दौरान महाराष्ट्र सरकार के जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विक्रो पाटिल, अमाविप राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री एस बालकृष्ण, एमयूएचएस (नासिक) के प्रतिकुलपति डा. निलिंद निरुम्भ, मोडिविजन के राष्ट्रीय संयोजक गौलिक ठवकर एवं अन्य।



इंदौर : दीप प्रज्ञविलित कर फार्माविजन राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करते मध्यप्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आर्युष मंत्री इंदर सिंह परमार, अमाविप राष्ट्रीय महानंत्री वीटेंड्र सिंह सोलंकी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. छगनभाई पटेल एवं अन्य।



राष्ट्रीय छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

वर्ष-47, अंक-06
अक्टूबर 2025

संपादक

आशुतोष भट्टनागर

संपादक मण्डल

संजीव कुमार सिन्हा

अवनीश सिंह

अभिषेक रंजन

अजीत कुमार सिंह

संपादकीय पत्राचार

राष्ट्रीय छात्रशक्ति

26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली - 110002.

फोन : 011-23216298

www.chhatrashakti.in

rashtriyachhatrashakti@gmail.com

www.facebook.com/Rchhatrashakti

www.twitter.com/Rchhatrashakti

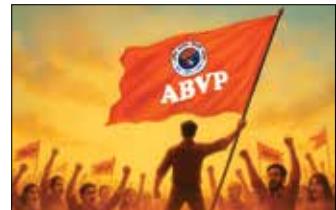
[www.instagram.com/ Rchhatrashakti](https://www.instagram.com/Rchhatrashakti)

स्वामी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक राजकुमार शर्मा द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नई दिल्ली - 110002 से प्रकाशित एवं औशियन ट्रेडिंग कं., 132 एफ. आई.ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110092 से मुद्रित। संपादक *पीआरबी अधिनियम के तहत समाचारों के चयन के लिए जिम्मेवार।

अभाविप का विजय

पथ

देश के विभिन्न विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में हुए छात्रसंघ चुनावों में अखिल भारतीय...



संपादकीय

04

Strengthening Bharat, Inspiring Generations

10

'स्वदेशी से ही हासिल होगी आर्थिक आत्मनिर्भरता'

13

A Constitutional Ideal or A Contested Goal

16

नए भारत की संभावनाओं पर मंथन

19

'देश की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में हो फार्मसी विद्यार्थियों का योगदान'

20

समग्र स्वास्थ्य सेवा पर चिंतन

21

छात्राओं को आत्मनिर्भर बना रहा है सर्जना निखार शिविर

22

देश में आरंभ हुए पांच डिजिटल विश्वविद्यालय

23

देश के 54 निजी विश्वविद्यालय डिफॉल्टर घोषित

24

अभाविप के संस्थापक सदस्य एवं शिक्षाविद

प्रा. वी. के. मल्होत्रा का निधन

25

...नहीं रहे अभाविप के पूर्व क्षेत्रीय संगठन मंत्री राधेश्याम जी

26

वैद्यानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त वृद्धिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

५

जयदाशमी 2025। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की एक शताब्दी की यात्रा पूरी हुई। निरंतर वर्धमान। कार्यकर्ताओं की संख्या, भौगोलिक व्याप और समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कदम-कदम बढ़ते हुए आज प्रगति के चरम पर पहुंचे। समय के साथ सब कुछ बदला। नहीं बदलीं तो मौलिक अवधारणा, संस्कृति बोध और समर्पण का भाव। इसके बल पर ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन बना। मानो एक विश्वाल वटवक्ष।

इस वटवृक्ष से शाखा-प्रशाखाएं फूटीं, पल्लवित हुईं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) भी एक प्रशाखा के रूप में विकसित हुई। इस वृक्ष से जीवन-रस प्राप्त किया, मूल्य और संगठन के स्रूत्र भी। समय की कसौटी पर सिद्ध इन सूत्रों का पालन करते हुए अभाविप भी शिक्षा क्षेत्र का प्रतिनिधि संगठन बना है। सदस्य संख्या और इकाइयों के विस्तार की दृष्टि से अन्य छात्र संगठन दूर तक नहीं ठहरते। चुनावी राजनीति के साथ ही अन्य अनेकों गतिविधियों के माध्यम से वर्ष भर सक्रिय रहने के कारण अभाविप विद्यार्थियों की पहली पसंद बनी है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में होने वाले छात्रसंघ चनावों के परिणाम इसे प्रमाणित करते हैं।

इस वर्ष सम्पन्न हुए छात्रसंघ चुनावों में अभिविष का विजय अभियान हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय से प्रारंभ होकर दिल्ली विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन बहुगुणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय (गढ़वाल), गुवाहाटी विश्वविद्यालय, असम विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, मंगलौर विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय आदि में अभिविष का केसरिया लहराया है।

विद्यार्थियों का यह विश्वास ही अभाविप पर बड़ी जिम्मेदारी डालता है। आज के प्रश्न केवल शिक्षा के प्रश्न नहीं बचे हैं। परिसरों की जीवन्तता तथा पाठ्यक्रमों का अद्यतन होना ही समस्याओं का अंत नहीं है। शिक्षा को रोजगारपरक बनाना और रोजगार के अवसर बढ़ाना भी समाधान नहीं है। सिकुड़ती-सिमटी इस दुनिया में हर दिन नए सवाल और नए प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। यह चुनौतियां भीतरी भी हैं और बाहरी भी। आज का नागरिक होने के कारण इनका सामना भी छात्र-युवाओं को करना है। वह समाधान का हिस्सा बन सके, इसके लिए परिषद को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

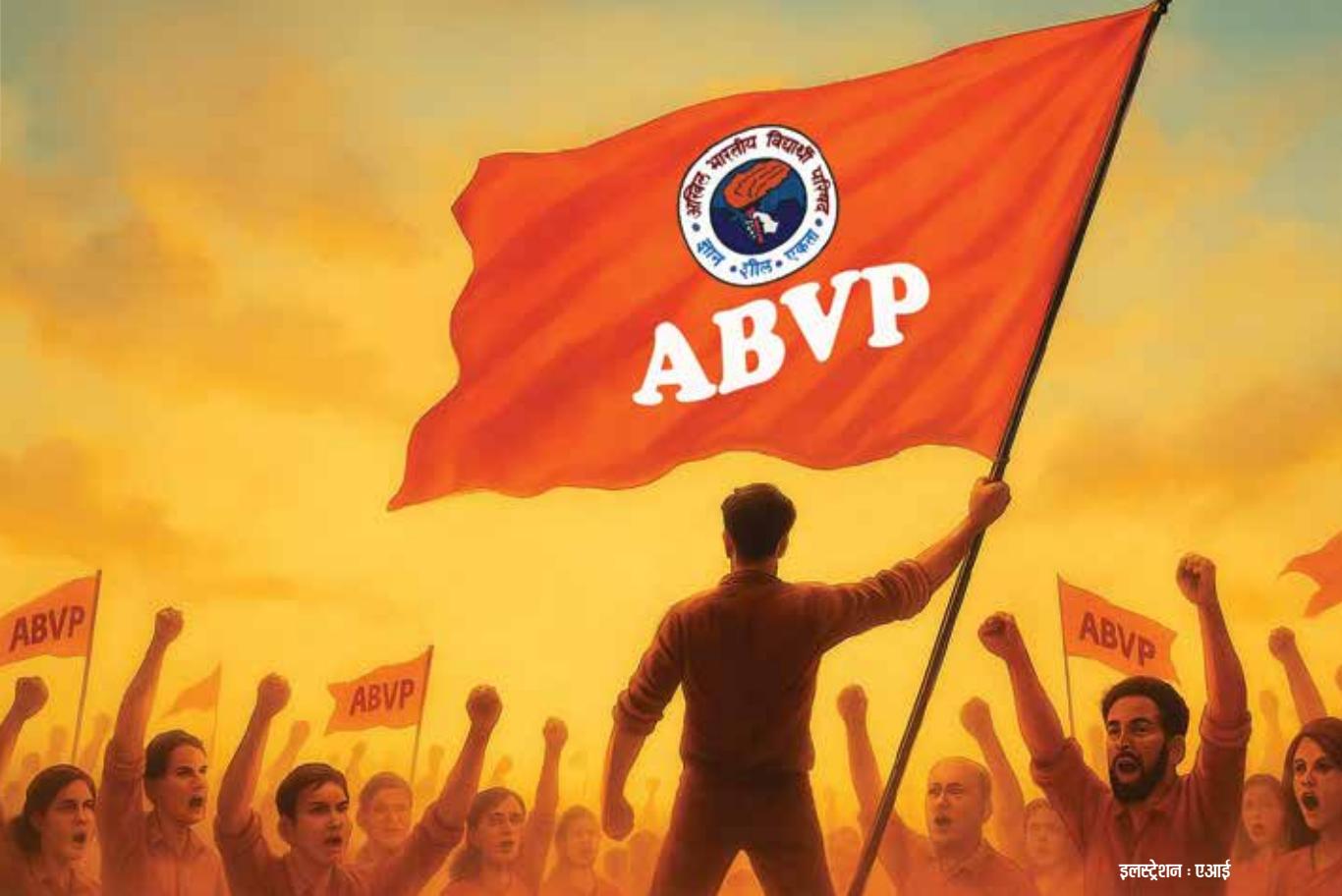
युवाओं की वैशिक दृष्टि गढ़ने में आज बाजार बड़ी भूमिका निभा रहा है। उसने एक आभासी विश्व खड़ा कर दिया है। इस विश्व में नैतिकता और परम्परागत मूल्यों का कोई स्थान नहीं है। बाजार, उत्तरदायित्वविहीन, सभी निषेधों को नकारने वाला, सभी वर्जनाओं को तोड़ने को उद्यत एक ऐसा युवा समाज गढ़ना चाहता है जो अपनी जड़ों से पूरी तरह कट चुका हो। इसके लिए अनास्था और अराजकता को मूल्यों के रूप में स्थापित करने का षड्यंत्र जरी है।

निस्संदेह यह वह मूल्य है, जिनको ढोते हुए पश्चिम अपने ही जाल में फँस चुका है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा अधिकतम उपभोग को सुख का मूल मान कर जीने का जोखिम उसने उठाया, परिणामस्वरूप अपनी परिवार व्यवस्था को खो बैठा। एक विद्वान लेखक ने वर्तमान पश्चिम को पिताविहीन विश्व कह कर संबोधित किया है। पश्चिम में अविवाहित मां और पितृविहीन संतानें बिखरे हुए समाज के अंधेरे परिदृश्य में से अपने लिए प्रकाश की एक ऐसी किरण की तलाश में तड़प रहे हैं, जिसके सहारे वह अपना जीवन काट सके। कथित मुक्ति के इसी अंधियारों को अब 'वोकिज्म' जैसी नई शब्दावली में भारत, जापान आदि संस्कृति आधारित समाजों की ओर धकेलने की कोशिश हो रही है। जिसमें भारत का एक छोटा वर्ग फँस चुका है।

आभासी विश्व में विचरण करती यह पीढ़ी सोशल मीडिया के द्वारा परोसे जा रहे झूठ को सच मान कर अपने इतिहास और संस्कृति से कट रही है। वह इस कुचक्र को पहचानने में सहायता चाहती है। उसे समान आयु का किन्तु संस्कृति और संस्कारों में रच-पगा एक ऐसा साथी चाहिए जो उसे इस भंवर से निकाल सके। अभिविष्ट कार्यकर्ता इस भूमिका को निभाकर देश की युवाशक्ति की ऊर्जा का नियोजन राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के महत्कार्य में कर सकते हैं, यही उनसे अपेक्षित भी है।

शभकामना सहित.

आपका
संपादक



इलेक्ट्रोनिक : एआई

अभाविप का विजय पथ

■ अंजीत कुमार सिंह

दश के विभिन्न विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में हुए छात्रसंघ चुनावों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने ऐतिहासिक बढ़त हासिल की है। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, हेमवंती नंदन बहुगुणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गौहाटी विश्वविद्यालय, असम विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, मंगलौर विश्वविद्यालय, हिमालच प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय (हरियाणा), पटना विश्वविद्यालय सहित देश के तमाम महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में हुए छात्र संघ चुनाव में छात्रों ने लगातार अभाविप के पक्ष में मतदान कर सिद्ध कर दिया कि उन्हें कोई भ्रमित नहीं कर सकता है।

अभाविप ने देश की राजधानी दिल्ली स्थित दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यक्ष सहित चार में से तीन पदों पर जीत का परचम लहराकर सिद्ध कर दिया कि परिसर में छात्रों की आवाज अभाविप ही है। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव, सांस्कृतिक सचिव और खेल सचिव पदों पर ऐतिहासिक विजय हासिल करके अभाविप ने जहां सभी को चौंका दिया, वहीं उत्तराखण्ड के अधिकांश महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में मिली जीत अभाविप के प्रति छात्रों के विश्वास को दर्शाने के लिए काफी है। पंजाब विश्वविद्यालय में भी पहली बार अध्यक्ष पद पर जीत हासिल कर अभाविप ने कई मिथकों को तोड़

दिया। इसके साथ ही गौहाटी विश्वविद्यालय में हासिल हुई शानदार विजय यह प्रमाणित करती है छात्र-युवा अभाविप के विचारों के साथ कदम से कदम मिलाकर राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की संकल्पना को पूरा करना चाहते हैं। हैदराबाद विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय और गौहाटी विश्वविद्यालय जैसे शैक्षिक परिसर पारंपरिक रूप से अभाविप के लिए चुनौतीपूर्ण माने जाते रहे हैं। ऐसे में इन परिसरों में मिली विजय महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में अभाविप का शानदार प्रदर्शन



अभाविप ने हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय (एचसीयू) छात्रसंघ चुनावों में निर्णायक जीत हासिल करते हुए सात वर्षों के लंबे अंतराल के बाद सभी छह पदों पर अपना कब्जा जमा लिया। यहां अध्यक्ष पद पर शिवा पालेपू (पीएचडी, एनिमल बायोलॉजी), उपाध्यक्ष पद पर देवेन्द्र (पीएचडी, लिंगिविस्टिक्स), महासचिव पद पर श्रुति प्रिया (पीएचडी, इकोनॉमिक्स), संयुक्त सचिव पद पर सौरभ शुक्ला (एमबीए), सांस्कृतिक सचिव पद पर वीनस (आएमए, लैंगिवेज साइंसेज) एवं खेल सचिव पद पर ज्वाला (पीएचडी, हिंदी) को जीत हासिल हुई। यह ऐतिहासिक परिणाम अभाविप कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, संगठनात्मक नेतृत्व की प्रभावी रणनीति और एचसीयू छात्रों द्वारा अपने परिसर के भविष्य को आकार देने में निर्भाई गई निर्णायक भूमिका का प्रमाण माना जा रहा है। छात्रों द्वारा दिया गया यह जनादेश उन तत्वों के लिए चिंताजनक कहा जा सकता है जो शैक्षिक

परिसरों में राजनीति की प्रयोगशाला बनाकर अराजकता, हिंसा और राष्ट्र-विरोधी विचारधारा को फलते-फूलते देखना चाहते हैं।

हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में विजय हासिल करने वाले छात्रनेताओं ने जीत का श्रेय वर्ष भर छात्रों के हित में कार्य करने वाले अभाविप के कार्यकर्ताओं को दिया। अध्यक्ष शिवा पालेपू एवं उपाध्यक्ष देवेन्द्र ने कहा कि छात्रों ने अभाविप गठबंधन के पैनल पर जो विश्वास व्यक्त किया है, उस पर वह पूरी तरह खरे उतरेंगे एवं छात्रों के हित के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। अबकी बार चुनाव में राज्य सरकार का वह निर्णय भी एक बड़ा मुद्दा बना, जिस निर्णय के अंतर्गत 400 एकड़ भूमि को नीलाम किया जाना था। इसमें विश्वविद्यालय की भूमि भी सम्मिलित थी। प्रकृति को दांव पर रख कर लिए गए निर्णय का अभाविप ने कड़ा विरोध किया था। अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री श्रवण बी राज के अनुसार एचसीयू के छात्रों ने अभाविप के कार्यों पर जीत सुनिश्चित की है।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में अभाविप की जीत

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव (डूसू) में हुए छात्रसंघ चुनाव में अभाविप ने केंद्रीय पैनल की 4 में से 3 सीटों पर अपना दबदबा बनाया, जबकि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) को मात्र एक सीट से संतोष करना पड़ा है। अबकी बार डूसू चुनाव में कुल 1,53,100 पंजीकृत मतदाताओं में से 60,272 छात्रों ने मतदान किया था। अभाविप ने डूसू चुनाव में अध्यक्ष, सचिव तथा संयुक्त सचिव पद पर जीत दर्ज कराई है। डूसू अध्यक्ष पद पर अभाविप के आर्यन मान 16,196 मतों के अंतर से, सचिव पद पर कुणाल चौधरी 7,662 मतों के अंतर से तथा संयुक्त सचिव पद पर दीपिका झा 4,445 मतों के अंतर से विजय हुए। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष पद पर यह दूसरी सबसे बड़ी जीत है।

अभाविप ने की छात्रों के दिलों की चोरी : वीरेन्द्र सिंह सोलंकी

अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री वीरेन्द्र सोलंकी ने छात्र संघ

चुनावों में मिली जीत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि चुनाव परिणाम से स्पष्ट हो गया कि भारत के जेन-जी का समर्थन अभाविप के साथ है। अभाविप ने छात्रों के दिलों की चोरी की, परिणामस्वरूप डूसू में चार में तीन पदों पर जीत मिली। देश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में अभाविप को मिली विजय लोकतंत्र के प्रति आस्थावान विचार की विजय है। अभाविप ने विद्यार्थियों-युवाओं के शिक्षा क्षेत्र के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए, युवाओं की आशाओं को दिशा दी है। कांग्रेस और एनएसयूआई ने डूसू चुनाव में डीयू के छात्र-छात्राओं को भ्रमित करने तथा जाति-क्षेत्र में बांटने का प्रयास किया, जिसको विद्यार्थियों ने पूरी तरह नकार दिया है।

डड्यंत्र विफल, विरोधियों को करारा जवाब : आर्यन मान

डूसू के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आर्यन मान के अनुसार डूसू चुनाव के दौरान एनएसयूआई ने उनके विरुद्ध दुष्प्रचार किया, लेकिन चुनाव परिणाम से उन्हें करारा जवाब मिल गया है। यह विजय युवा पीढ़ी की उस राष्ट्रनिष्ठ चेतना की प्रतिध्वनि है, जो भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रनिर्माण के संकल्प को सर्वोपरि मानती है। विद्यार्थियों ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वह देशविरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले तत्वों को करारा जवाब देने में सक्षम हैं।



हर समय छात्रहित के लिए तत्पर : कुणाल चौधरी

डूसू के नवनिर्वाचित सचिव कुणाल चौधरी के अनुसार वह दिल्ली विश्वविद्यालय के हर छात्र को वोट देने के लिये धन्यवाद देते हैं। वह छात्रों को विश्वास दिलाना चाहेंगे कि जब भी उन्हें मेरी जरूरत होगी, वह उनके साथ खड़े होंगे। यह परिणाम इस बात का प्रमाण है कि आज का युवा भ्रम और प्रपंच से ऊपर उठकर राष्ट्रहित, छात्रहित और पारदर्शिता की राह चुन रहा है। कांग्रेस और एनएसयूआई ने वर्षों से जिस तरह भ्रष्टाचार,



अवसरवाद और कुठित मानसिकता को संस्थानों पर थोपने का प्रयास किया, उसे विद्यार्थियों ने नकार दिया है। यह जीत उस संकल्प की गूँज है कि अब विश्वविद्यालयों में केवल वही राजनीति स्वीकार्य होगी जो राष्ट्र निर्माण की धारा में विद्यार्थियों को जोड़ती है, न कि तोड़ने का काम करती है।

डीयू के सभी छात्रों की जीत : दीपिका झा

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की नवनिर्वाचित संयुक्त सचिव दीपिका झा के अनुसार यह सिर्फ उनकी जीत नहीं है, यह डीयू के सभी छात्रों की जीत है, खासकर जो प्रवासी हैं और डीयू में पढ़ रहे हैं। वह अभाविप और डीयू के छात्रों को उनके समर्थन के लिए सारा श्रेय देती है। डूसू में अभाविप दशकों से छात्राओं को न केवल सशक्त प्रतिनिधित्व देती रही है, बल्कि उनकी जीत भी सुनिश्चित कराती आई है। उनकी जीत भी संगठन की कुशल रणनीति और कार्यकर्ताओं के समर्पण का परिणाम है। पिछले दस वर्षों के चुनाव परिणाम पर दृष्टि डालें तो डूसू में लगातार अभाविप की ही छात्र प्रत्याशी निर्वाचित होती रही हैं और यह परंपरा इस बार भी कायम रही।



दिल्ली के महाविद्यालय छात्रसंघ चुनावों में भी अभाविप का परचम

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशियों ने दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालयीन छात्रसंघ चुनावों में भी जीत का परचम का लहराया। कुल 52 महाविद्यालय के छात्रों ने इस चुनाव में भाग लेते हुए केंद्रीय पैनल और अभाविप काउंसलर पदों के लिए अपने मत दिए, जिसमें 20 से अधिक महाविद्यालयों में अभाविप ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है, वहीं कुल 152 से अधिक महाविद्यालयीन छात्रसंघ पदाधिकारी अभाविप से निर्वाचित हुए हैं। चुनाव के नतीजों में अधिकांश महाविद्यालयों में अभाविप का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभाविप और भगिनी निवेदिता अभाविप ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि

| आवरण कथा |

एसजीटीबी खालसा और जाकिर हुसैन में भी अभाविप को विजय हासिल हुई। इसके अलावा कई अन्य संस्थानों में भी अभाविप उम्मीदवार सफल रहे।

उत्तराखण्ड में अभाविप का बोलबाला



उत्तराखण्ड के विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में संपन्न छात्रसंघ चुनावों में अभाविप को बड़ी सफलता मिली है। संपन्न हुए छात्रसंघ चुनाव में अभाविप ने 57 अध्यक्ष, 52 उपाध्यक्ष, 47 महासचिव, 51 कोषाध्यक्ष, 50 सह सचिव, 62 विश्वविद्यालय प्रतिनिधि, 6 सांस्कृतिक सचिव, 6 छात्रा उपाध्यक्ष सहित कुल 331 पदों पर जीत का परचम फहराया।

अभाविप उत्तराखण्ड के प्रदेश मंत्री ऋषभ रावत के अनुसार यह विजय केवल परिषद की विजय नहीं, बल्कि हर उस विद्यार्थी की विजय है जो राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानता है, संघर्ष और संगठन को ही जीवन का मूल मत्र मानता है। सैन्य भूमि उत्तराखण्ड में शहीद भगत सिंह जी की जयंती के दिन मिली यह विजय वीर शहीदों के आशीर्वाद से मिली विजय है और यह जीत पहाड़ की जीत है। छात्रशक्ति ने अपने अपार स्नेह और आशीर्वाद से एक बार फिर यह प्रमाणित कर दिया है कि उनका अडिग विश्वास सदैव उस संगठन के साथ रहा है, जो निष्ठापूर्वक छात्रहितों की रक्षा और राष्ट्रनिर्माण के पथ पर अग्रसर रहता है।

राज्य के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय (श्रीनगर) में अध्यक्ष पद पर महिपाल बिष्ट एवं जी. आर. पद पर विदिशा सिंह ने जीत हासिल की। इसी तरह देहरादून स्थित डीएवी कालेज

में छात्रशक्ति ने यह सिद्ध कर दिखाया कि उनका अटूट विश्वास केवल अभाविप पर है। अभाविप ने श्री देव सुमन विश्वविद्यालय परिसर (ऋषिकेश), डा. पीताम्बर दत्त बर्थवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय (कोटद्वार), एलएसएम (पिथौरागढ़), एमबीपीजी कालेज (हल्द्वानी), राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय (गैरसैंण) में भी छात्रसंघ चुनाव में विजय हासिल की। हल्द्वानी के एमबीपीजी कालेज में अध्यक्ष पद पर अधिषेक गोस्वामी का मिली प्रचंड जीत ने यह सिद्ध कर दिया कि यह विजय केवल मतपेटियों की गिनती नहीं, बल्कि छात्रों के हृदयों में रचा-बसा परिषद के प्रति विश्वास है।

गौहाटी विश्वविद्यालय में लहराया भगवा



गौहाटी विश्वविद्यालय में हुए छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर गुंजन डेका, महासचिव पद पर प्रबल ज्योति शर्मा, संगीत सचिव पद पर प्रीतिमलिला का खनिकर, खेल सचिव (पीजी) पद पर आयुष गौतम, खेल सचिव (यूजी) पद पर भूयसी बरुवा, खेल सचिव प्रमुख पद पर कांगेस्वर बोरो एवं व्यायामशाला सचिव पद अभाविप के पूर्वा बरगोहाइ की जीत हासिल हुई। परिणामों की घोषणा होने के बाद अभाविप के सभी विजयी प्रत्याशियों का स्वागत अभाविप के प्रदेश मंत्री हेराल्ड मोहन ने प्रदेश कार्यालय में किया। अध्यक्ष पद पर 755 वोटों से जीत दर्ज कराने वाले नवनिर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष गुंजन डेका के अनुसार यह जीत उन आम छात्रों की जीत है, जिन्होंने राष्ट्रवाद को चुना है। नवनिर्वाचित महासचिव प्रबाल ज्योति शर्मा के अनुसार

लगातार दूसरी बार छात्रों ने अभाविप प्रत्याशियों के ऊपर भरोसा जताया है।

अभाविप के प्रदेश मंत्री हेरल्ड मोहन के अनुसार असम की जेन-जी जेनरेशन भी राष्ट्रवाद के साथ खड़ी है। छात्र-युवाओं को भड़काकर देश में अराजकता फैलाकर सत्ता पाने का सपना पालने वाली कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई का पूरी तरह से सफाया हो गया है। 18 मार्च 2024 को जिन नकारात्मक शक्तियों ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के नाम पर प्रदर्शन के बहाने मां कामाख्या एवं लाचित बरफुकन की तस्वीर वाली फोटो जलाकर अपमान किया था, उन सभी ताकतों को गौहाटी विश्वविद्यालय के छात्रों ने करारा जवाब देते हुए नकार दिया है।

हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्रसंघ के सभी पद पर अभाविप



हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में अभाविप ने सभी पदों पर जीत हासिल की है। छात्रसंघ के 20 में से 18 पदों पर अभाविप को निर्विरोध चुना गया, जबकि अन्य दो पर गत 4 अक्टूबर को हुए चुनाव में जीत हासिल हुई। अभाविप हिमाचल प्रदेश मंत्री नैसी अटल के अनुसार अभाविप ने केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के छात्र संघ चुनावों में ऐतिहासिक सफलता अर्जित की है। इस चुनाव में सभी विभागीय प्रतिनिधियों पर अभाविप की जीत मिली। यह परिणाम संगठन की मजबूत पकड़ और विद्यार्थियों के अदृढ़ विश्वास का प्रतीक है।

मंगलौर विश्वविद्यालय में भी छा गई अभाविप



कर्नाटक के प्रसिद्ध मंगलौर विश्वविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव में पुनः अभाविप को जीत मिली है। अभाविप ने सभी छः पदों पर विजय प्राप्त की है। अभाविप ने इस जीत को एनएसयूआई की करारी हार बताते हुए कहा कि भारत के जेन-जी ने समाज और विश्वविद्यालय में भ्रम पैदा करने वाली शक्तियों को नकार दिया है। भारत के युवा राष्ट्र के विकास के साथ है। अभाविप को मिली यह जीत विश्वविद्यालय के छात्रों का अभाविप के प्रति प्रेम को दर्शाती है। छात्रों के स्नेह के कारण ही मंगलौर विश्वविद्यालय में अभाविप लगातार विजय हासिल करती आ रही है।

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के डीआर चुनावों में भी बजा अभाविप का डंका



हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में हुए विभागीय प्रतिनिधि (डीआर) चुनावों में अभाविप ने 34 विभागों के 40 डीआर पदों में से 34 डीआर पदों पर विजय हासिल कर विश्वविद्यालय परिसर में अपना परचम लहराया। यह जीत विद्यार्थियों के विश्वास, अभाविप के वर्षों के समर्पण और छात्र हित की नीतियों का परिणाम मानी जा रही है। ■

Strengthening Bharat Inspiring Generations

■ PAWAN SHARMA

Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), the largest voluntary social and cultural organisation in the world, enters its centenary year in 2025. This is not merely the completion of a hundred years on the calendar, but a century of relentless commitment, sacrifice and sewa (selfless service) towards the motherland. It is a moment of profound national significance, a landmark that transcends organisational achievement.

When Dr. Keshav Baliram Hedgewar laid the foundation of the RSS in Nagpur on Vijayadashami in 1925, he envisioned an organisation that would silently and selflessly dedicate itself to the regeneration of Indian society. His belief was simple yet powerful: a strong, disciplined and morally upright society would be the foundation of a strong nation. What started as a small initiative with a handful of swayamsevaks (volunteers) has now become a global movement of millions, deeply influencing India's social, cultural and political life.

As RSS completes 100 years, it stands as a beacon of resilience and inspiration. It has faced bans, criticism, suppression and countless challenges, yet emerged stronger with every test. Its growth from modest shakhas in local mohallas to a worldwide presence is testimony to its clarity of vision and steadfastness of mission. The centenary celebrations are therefore not just about looking back, but also about reaffirming the timeless values of discipline, unity, cultural pride and above all, sewa.

FOUNDATIONAL VISION : HEDGEWAR'S DREAM

The early 20th century was a time of turbulence for India. The freedom struggle was gaining momentum, but disunity, caste divisions and lack of social cohesion weakened society from within. Dr. Hedgewar, a nationalist deeply influenced by nationalistic thought's, realized that India's challenges were not merely political but civilizational.

He believed that political independence would be incomplete without social regeneration. The RSS was therefore conceived not as a political party but as a cultural and social movement dedicated to character-building. The organisation emphasized discipline, physical fitness and moral integrity through daily shakhas (regular gatherings), where swayamsevaks participated in physical drills, discussions and patriotic songs.

The core philosophy was "Sangathan" (organization). Dr. Hedgewar believed that a united society-where individuals rose above caste, creed and selfish interests-would be India's greatest strength. His mission was to instill in ordinary citizens a sense of pride in their cultural heritage, duty towards society and readiness to serve the nation selflessly.

This foundational vision became the guiding light for generations of swayamsevaks. Over the decades, the RSS nurtured countless leaders, activists and social workers who carried this torch into diverse spheres of Indian life-education, politics, social reform, disaster relief and beyond.

RSS THROUGH THE DECADES : A JOURNEY OF RESILIENCE

PRE-INDEPENDENCE (1925–1947)

BUILDING THE BASE

In its early years, the RSS focused on organizing disciplined shakhas across towns and villages. Dr. Hedgewar's belief was not in loud slogans but in silent, consistent work. By the 1940s, RSS had spread to many parts of India, attracting young men who were drawn to its sense of discipline and patriotism.

During the freedom struggle, RSS swayamsevaks participated in local resistance, relief during natural calamities, and mobilization of people. Though not directly aligned with any political party, the organisation was deeply nationalist and worked to instill pride in India's heritage, which colonial rulers had sought to undermine.

POST-INDEPENDENCE (1947–1960)

TRIALS AND PERSEVERANCE

The partition of India in 1947 tested the RSS like never before. Amidst the horror of communal violence, swayamsevaks were at the forefront of relief operations, rescuing thousands of families and helping rehabilitate refugees. However, in the aftermath of Mahatma Gandhi's assassination in 1948, the RSS was banned, despite no evidence linking it to the crime.

This period was one of great trial. Yet, instead of breaking, the organization grew stronger. The second Sarsanghchalak, Guruji Golwalkar, emphasized internal consolidation, discipline and expansion of shakhas. He envisioned the Sangh as a moral and cultural force that would endure beyond immediate politics.

EXPANSION AND INFLUENCE (1960–1980)

By the 1960s, RSS had expanded its activities significantly. Affiliates such as Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS), Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP), Vanvasi Kalyan Ashram and Seva Bharati extended its

outreach into labor rights, student movements, tribal welfare and social service.

During the 1975-77 Emergency, RSS played a key role in resisting authoritarian rule, with thousands of swayamsevaks jailed for their commitment to democracy. The organisation's silent strength inspired citizens across the country and cemented its reputation as a force for national integrity.

A GLOBAL MOVEMENT (1990–PRESENT)

With the Ram Janmabhoomi movement in the 1980s and 1990s, the RSS emerged at the center of India's cultural awakening. The movement was not just about a temple but about reclaiming national pride. Simultaneously, the organization's international wings spread rapidly, with swayamsevaks establishing shakhas across the world.

In the 21st century, the RSS has adapted to modern challenges while retaining its core principles. Its influence on education, rural development, disaster relief and environmental consciousness has grown. Its emphasis on Aatmanirbharta (self-reliance) resonates with the national vision of a strong, self-confident India.

RSS AS A SOCIAL FORCE : SERVICE BEYOND BOUNDARIES

One of the most remarkable aspects of the RSS is its sewa-oriented mindset. The organisation has always believed in working silently during times of crisis. Whether it was the Bengal famine, earthquakes in Latur and Bhuj, floods in Assam, the Kedarnath disaster, or the COVID-19 pandemic, swayamsevaks have always been first responders.

The Seva Bharati network of health centers and rural development programs is one of the largest voluntary service initiatives in India. In tribal and remote areas, swayamsevaks have worked tirelessly to promote education, healthcare, and skill development, often under extremely challenging conditions.

The RSS approach is unique—it does not

believe in charity, but in empowerment. By focusing on self-reliance, dignity and social harmony, its work uplifts communities rather than creating dependency.

RSS AND NATION-BUILDING : THE IDEOLOGICAL CONTRIBUTION

The RSS has always maintained that nation-building begins with man-making. Its emphasis on individual character, discipline and integrity has shaped countless citizens who contribute to society in diverse ways.

In a democratic setup, the RSS has played the role of a silent moral guide. It has never sought power for itself, yet inspired many who went on to serve India in public life. The ideological clarity of the RSS is rooted in the idea of "Ek Bharat, Shreshtha Bharat"-a united, culturally strong and self-confident nation.

The Sangh has also been instrumental in social harmony initiatives. Through programs for samajik samrasta and rural development, it has consistently worked against divisive forces. Its vision of Hindutva is not exclusionary but civilizational, rooted in the idea of cultural unity and respect for diversity.

GLOBAL DIMENSIONS OF RSS

The RSS is not confined to India's borders. Over the decades, it has inspired the creation of organizations like HSS (Hindu Swayamsevak Sangh) abroad, which work with Indian diaspora communities. From the United States to the UK, from Australia to Kenya, these groups nurture Indian values, traditions and cultural pride among overseas Indians.

In an age of globalization, the RSS has played a vital role in connecting the diaspora to their roots, ensuring that cultural pride and national identity remain strong, even thousands of miles away.

RSS @100 : A NATIONAL FESTIVAL

The centenary year of the RSS is not just a celebration for swayamsevaks but a national

festival for all Indians. It symbolizes a hundred years of perseverance against odds, silent service and deep commitment to the nation.

Programs across India are highlighting the Sangh's contribution to society, with special focus on youth and women participation. From cultural festivals to social service drives, the centenary is being marked with activities that reaffirm the Sangh's mission for the next century.

VISION FOR THE FUTURE (TOWARDS 2047)

As India approaches its centenary of independence in 2047, the role of the RSS becomes even more crucial. The challenges of modern times-climate change, rapid urbanization, social fragmentation, global competition-require strong societal values and unity.

The RSS vision for the future is clear :

- Youth empowerment through character-building and values.
- Social harmony by breaking caste barriers and ensuring inclusivity.
- Self-reliant Bharat, aligned with the vision of Aatmanirbhar Bharat.
- Cultural pride rooted in Sanatan values yet adaptable to modern realities.
- Global leadership as Bharat becomes a Vishwaguru.

CONCLUSION(A CENTURY OF INSPIRATION)

The journey of the Rashtriya Swayamsevak Sangh is the journey of a nation reclaiming its self-confidence. From its humble beginnings in 1925 to becoming the largest volunteer organisation in the world, the RSS has lived by its motto of commitment, sacrifice and sewa.

This centenary is not just an institutional milestone-it, reminds us of the timeless principles that bind us as a society: unity, discipline, service and cultural pride. As we step into the next century, the RSS remains a guiding light, inspiring millions to dedicate themselves to the service of Bharat Mata. ■

(Author is former State organising secretary of ABVP-J&K)

‘स्वदेशी से ही हासिल होगी आर्थिक आत्मनिर्भरता’

२१ ताब्दी वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा किए गए पंच परिवर्तन आह्वान में सम्मिलित स्वदेशी आचरण पर जोर देते हुए स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठक कश्मीरी लाल का कहना है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आर्थिक आधार पर आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। यह आत्मनिर्भरता स्वदेशीकरण से ही हासिल होगी। देश की जनता को स्वदेशी वस्तुओं के प्रति आग्रह रखते हुए प्रत्येक क्षेत्र में स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि संघ की स्वदेशी से जुड़ी अवधारणा आगामी शताब्दियों की परिस्थितियों पर विचार करके निर्मित हुई है, जिसका एकमात्र लक्ष्य भारतीय उत्पादों को पूरी दुनिया तक पहुंचाने और देश को आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाने पर केंद्रित है।

राजधानी दिल्ली में भारत नीति प्रतिष्ठान द्वारा ‘वैश्वीकरण पर संकट और स्वदेशी का उभार’ विषय पर 27 सितंबर को आयोजित एक व्याख्यान में स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठक कश्मीरी लाल ने कहा कि ब्रिटिश सत्ताकाल के दौरान देश में पहला स्वदेशी आंदोलन हुआ था। 1905 में हुए स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार और भारत के स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना था। यह स्वदेशी आंदोलन शोषण और ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शासन सम्बन्धी नीतियों के विरुद्ध भी था। इसके बाद देश में दूसरा स्वदेशी आंदोलन 1991 में प्रारंभ हुआ, जो विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ), डंकन प्रस्ताव एवं पेटेंट संबंधी नीतियों के विरोध में था। देश में जबरन थोपे जा रहे वैश्वीकरण के विरोध में हुए दूसरे स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य भी देश में बनी वस्तुओं को प्रोत्साहित करना था। लेकिन समय परिवर्तन के साथ अब स्वदेशी के मुद्दे में बदलाव आया है। पहले अचार, मुरब्बा, चिप्स का मुद्दा उठाया जाता था, लेकिन अब स्वदेशीकरण का प्रश्न माइक्रोचिप्स,

हैंडलूम, मशीनों सहित सेवा क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र एवं इंटरनेट पर हावी विदेशी कंपनियों के विरुद्ध खड़ा हुआ है।

विश्व के कुछ देशों द्वारा भारत के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंधों सहित अन्य आर्थिक दबावकारी नीतियों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका दोनों ही बड़ी शक्तियां हैं। दोनों ही भारत के आर्थिक हितों के विपरीत काम कर रहे हैं। ऐसे में एक की डम्पिंग नीति और दूसरे की टैरिफ नीति से उत्पन्न होने वाले संकटों से देश को बचाना होगा। वर्तमान समय में आर्थिक संकटों का स्वरूप बदल गया है। उन्होंने बताया कि 2014 के बाद से एक नियोजित रणनीति के साथ कदम बढ़ाते हुए देश स्वदेशीकरण की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। 1905 में 7 अगस्त को आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन को ध्यान में रखते हुए, जब देश में 7 अगस्त 2015 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई तो स्वदेशी की वही चेतना सभी को पुनः याद आई। भारतीय योग को ध्यान में रखकर घोषित किया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी स्वदेशी का एक प्रयोग कहा जा सकता है। मोटे अनाज (मिलेट) के उपयोग के लिए किया गए आह्वान को भी स्वदेशीकरण की प्रक्रिया से जोड़ कर देखा जा सकता है।

स्वदेशी जागरण मंच द्वारा चलाए जा रहे स्वावलंबी भारत अभियान के मुख्य संरक्षक श्रीधर वेम्बू का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि तकनीकी क्षेत्र के स्वदेशीकरण में उनकी भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। उन्हें भारत के नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्र में सॉफ्टवेयर और उत्पाद विकास कार्यों को ले जाने के लिए पहचाना जाता है। उनकी कंपनी द्वारा बनाए गए कई ऐप्लिकेशन ऐसे हैं, जिसे दुनिया के विकसित देश खरीद रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कोरोना काल में देश ने ‘वोकल फॉर लोकल’ अर्थात् बाहर से आयात कम करने का

नारा लगाया। उस दौरान जब विश्व के विकसित देशों ने कोरोना वैक्सीन देने से इंकार कर दिया, तब भारत ने दो वैक्सीन बनाई। स्वदेशीकरण की इस प्रक्रिया को प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम ‘मन की बात’ में लगातार बढ़ावा देने का कार्य किया। प्रत्येक माह मन की बात कार्यक्रम में कहीं न कहीं आत्मनिर्भर भारत का, वोकल फॉर लोकल एवं स्वदेशी का वर्णन आता रहा है और मेड इन इंडिया या स्वदेशी को प्राथमिकता दी जाती रही है। लेकिन यहां पर समझना यह भी आवश्यक है कि मेड इन इंडिया या स्वदेशी का अर्थ केवल भारत में बने उत्पाद से नहीं है, बल्कि इसका अर्थ भारतीयों द्वारा बने उत्पाद से है। स्वदेशी वस्तुओं के लिए यह आग्रह

रखना चाहिए।

रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि जो भारत किसी समय रक्षा उत्पादों के आयात पर निर्भर था, वही भारत अब स्वदेशी रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रहा है। यह पूर्व निर्धारित रणनीति का परिणाम है। देश के सहकारिता क्षेत्र की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व के देशों में भारत अपने सहकारिता क्षेत्र से जुड़े उत्पाद बेच रहा है। इसका लाभ सहकारिता क्षेत्र से संबंधित सभी लोगों को मिल रहा है। देश के सहकारिता क्षेत्र में बहुत बड़ी ताकत छिपी हुई है और डा. वर्गीज़ कुरियन जैसे और लोगों की आवश्यकता है, जिससे सहकारिता क्षेत्र को

इंटरनेट पर बढ़त बनाती स्वदेशी प्रौद्योगिकी कंपनी जोहो

जोहो रतीय प्रौद्योगिकी कंपनी जोहो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे दिग्गज इंटरनेट आधारित प्रौद्योगिकी कंपनी का बड़ा विकल्प बनकर सामने आई है। जोहो कॉर्पोरेशन भारत की पहली ऐसी स्वदेशी कंपनी है, जो इंटरनेट आधारित व्यावसायिक प्रोग्राम (सॉफ्टवेयर) बना रही है। कंपनी की स्थापना 1996 में श्रीधर वेबू और टोनी थॉमस द्वारा की गई थी, जो अब वैश्विक स्तर पर भारतीय कंपनी के रूप में अपनी विशेष पहचान बना चुकी है। ऑनलाइन जोहो ऑफिस सुइट के लिए जानी जाने वाली कंपनी का वैश्विक मुख्यालय तमिलनाडु स्थित चेन्नई में है। जानकारी के अनुसार 1996 से लेकर 2011 तक कंपनी को ‘एडवेंटनेट इंक’ के नाम से जाना जाता

था और यह नेटवर्क प्रबंधन सॉफ्टवेयर प्रदान करती थी। 2009 में कंपनी का नाम बदलकर जोहो कॉर्पोरेशन कर दिया गया। कॉर्पोरेशन के स्वदेशी उत्पादों में जोहो बुक्स, अकाउंटिंग एप्लिकेशन जोहो वर्कप्लेस, एंटरप्राइज सहयोग प्लेटफार्म जोहो सर्वे, एक ग्राहक अनुभव प्रबंधन उपकरण और जोहो पीपुल के साथ ही एचआर प्रबंधन प्लेटफॉर्म शामिल हैं। जोहो ट्राईडॉट उपयोगकर्ताओं को इमेल, संदेश, कॉल एवं वीडियो कॉल आदि के माध्यम से विभिन्न चैनलों पर संवाद करने में मदद करता है। जोहो द्वारा विकसित अरतई मैसेजिंग एप वैश्विक चैटिंग दिग्गजों के लिए एक ‘मेड-इन-इंडिया’ विकल्प के रूप में स्थापित कर रहा है। ‘अरतई’ नाम तमिल भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है “सामान्य बातचीत”। यह एप टेक्स्ट मैसेजिंग, वॉयस और वीडियो कॉल और मीडिया शेयरिंग के साथ-साथ ‘स्टोरीज’ और ‘चैनल्स’ जैसी सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें वॉयस और वीडियो कॉल के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन पहले से ही मौजूद है। फिलहाल भारत की स्वदेशी कंपनी जोहो लगातार इंटरनेट पर अपनी बढ़त बना रही है। वर्तमान में विश्व के 10 करोड़ से भी अधिक लोग जोहो के तकनीकी उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं। ■



अर्थव्यवस्था को मिली गति एवं आम आदमी को राहत

टेंशन के अर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ ही कर व्यवस्था को सरल एवं आम आदमी को राहत देने के उद्देश्य से 56वीं वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने अगली पीढ़ी के सुधारों के साथ जीएसटी-2.0 को लागू कर दिया है। जीएसटी-2.0 व्यवस्था के अंतर्गत करों की दर में किए गए परिवर्तन गत 22 सितंबर से देश में प्रभावी हो गए। जीएसटी 2.0 में करों की दर को चार स्लैब क्रमशः 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत में रखा गया है। नई व्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं के लिए 5 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत और अन्य के लिए 18 प्रतिशत दर शामिल है।

तंबाकू एवं पान मसाला जैसी वस्तुओं के लिये 40 प्रतिशत दर निर्धारित की गई है। केंद्र सरकार का मानना है कि व्यापक रूप से जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने और इससे जुड़ी प्रक्रिया में सुधार का उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है। जीएसटी-2.0 के माध्यम से होने वाले व्यापक सुधार आम जनता के जीवन को बेहतर बनाने के साथ ही छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए कारोबारी सुगमता सुनिश्चित करेंगे। जानकारी हो कि 101वें संविधान संशोधन अधिनियम-2017 द्वारा देश में लागू जीएसटी कर व्यवस्था वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। यह एक मूल्य-योजित कर (वेट) है, जिसने केंद्र और राज्यों द्वारा पहले लगाए जाने वाले अनेक अप्रत्यक्ष करों का स्थान लिया है। ■



और अधिक गति मिल सकेगी। स्वालम्बन के लिए सहकारिता क्षेत्र को और विकसित करना होगा।

प्रत्येक क्षेत्र में स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी जागरण मंच द्वारा चलाए जा रहे अभियान के विषय में उन्होंने बताया कि मंच द्वारा प्रत्येक दुकानदार को एक स्टीकर दिया जा रहा है, जिसे दुकान पर लगाकर दुकानदार अपने ग्राहकों को स्वदेशी वस्तुओं की खरीद के लिए प्रेरित करता है। साथ ही स्वदेशी और विदेशी सामानों की सूची भी प्रदान की जा रही है। जानकार आश्चर्य होगा कि देश में अब स्वदेशी वस्तुओं की सूची बढ़ती जा रही है। भारतीय उद्यमियों की हिम्मत और स्वदेशी के प्रति लोगों के बढ़ते आग्रह के कारण विदेशी चीजें भी स्वदेशी बनती जा रही हैं।

उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि वर्तमान में जो स्वदेशी है, वही लेना चाहिए। लेकिन मजबूरी में जो वस्तु स्वदेशी उपलब्ध नहीं है, उस वस्तु को विदेश से लेने में कोई हानि नहीं है। देश में स्वदेशी की भावना

को दृढ़ करने के लिए सोशल मीडिया के उपयोग की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मौलिक और अच्छी पोस्ट के माध्यम से वह लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही इस कार्य में समाज के नेतृत्व को भी साथ में लिया जा रहा है। अर्थिक क्षेत्र में अनैतिक व्यवहारों के विरुद्ध लड़ाई जारी है। इसमें भारत का बहुत बड़ा विजन है। लेकिन इसके लिए शक्ति होना भी आवश्यक है। भगवान राम को तीर की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन रावण को मारना है तो तीर की आवश्यकता है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण जो स्वयं धर्म के अवतार थे, इसके बावजूद उनको पता था कि पापियों को मारने के लिए स्टीकर रणनीति भी अपनानी पड़ेगी। इसलिए भारत को भी वह रणनीति अपनानी पड़ेगी और यह बुराई का समाप्त करके अच्छाई को बढ़ाने के लिए होगा। आज जो वैश्विक मिशन है, उसके लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। ■

(प्रस्तुति : संजय दीक्षित)

UNIFORM CIVIL CODE

A CONSTITUTIONAL IDEAL OR A CONTESTED GOAL

■ DR. PRADEEP KUMAR

The Uniform Civil Code (UCC) is a proposed law in India that aims to replace religion-based personal laws with a common set of civil laws applicable to all citizens. It seeks to regulate personal matters such as marriage, divorce, inheritance, and adoption, ensuring uniformity and equality across different communities, regardless of religion or gender. The concept of "one country, one rule" resonates with the idea of UCC, emphasizing a single legal framework for all. The term 'Uniform Civil Code' is explicitly mentioned in Article-44 of the Indian Constitution, which states: "The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India."

WHY DOES INDIA NEED A UNIFORM CIVIL CODE?

GENDER EQUALITY & WOMEN'S RIGHTS

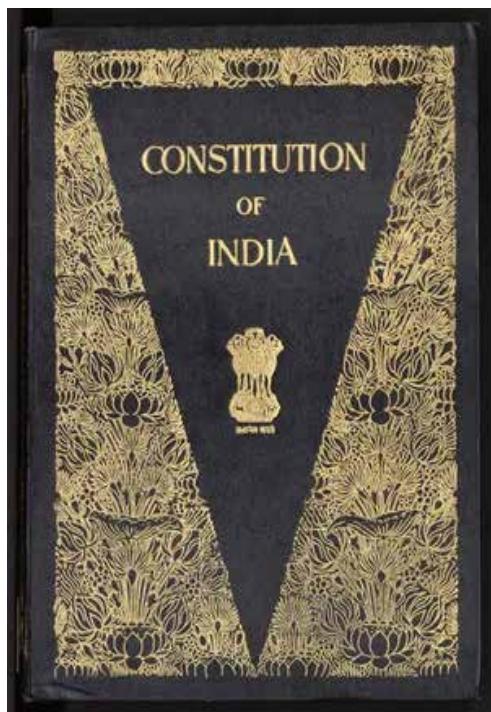
One of the strongest arguments for implementing UCC is to eliminate gender-based discrimination in personal laws.

Historically, religious laws have been unequal, particularly for women. For instance, before the Supreme Court's intervention, Muslim men could instantly divorce their wives using the practice of triple talaq, leaving women with no financial security. Similarly, until 2005, Hindu women did not have equal inheritance rights over ancestral property. By enforcing a UCC, all women—regardless of religious background—would receive equal rights in marriage, divorce, maintenance, and inheritance.

NATIONAL INTEGRATION

Currently, different religious communities in India follow their respective personal laws: Hindus adhere to Hindu personal laws, Muslims follow Sharia-based laws, and Christians

abide by Christian marriage and divorce laws. This creates legal disparities and reinforces divisions among communities. A UCC would unify these different legal systems, ensuring equal treatment for all citizens under a common legal framework.



MAJOR HISTORICAL PROTESTS IN INDIA REGARDING UCC

HINDU CODE BILL CONTROVERSY (1948-1956)

After India's independence, the Hindu Code Bill was introduced by Dr. B. R. Ambedkar and Prime Minister Jawaharlal Nehru to reform Hindu personal laws regarding marriage, inheritance and divorce for gender equality. However, conservative Hindu groups fiercely opposed the bill, viewing it as an attack on religious traditions. The backlash led to Ambedkar's resignation in 1951. Eventually, in 1956, the bill was passed as separate laws, bringing progressive reforms for Hindu women. However, these reforms applied only to Hindus, leaving other religious communities untouched, fueling the debate on the need for a Uniform Civil Code.

DR. B. R. AMBEDKAR AND OTHER FRAMERS OF THE INDIAN CONSTITUTION ENVISIONED THE UCC AS A MEANS TO ENSURE EQUALITY FOR ALL CITIZENS, REGARDLESS OF RELIGION.

SHAH BANO CASE & BACKLASH (1985-1986)

The landmark Shah Bano case brought the UCC debate to national attention. Shah Bano, a 62-year-old Muslim woman, was divorced through triple talaq and denied alimony. She filed a case and the Supreme Court ruled in her favor under Section 125 of the Criminal Procedure Code (CrPC), which grants maintenance rights to all women. However, the verdict faced massive protests from Muslim religious

leaders, who saw it as an infringement on Sharia law. The Rajiv Gandhi government, under pressure, passed the Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act-1986, which effectively nullified the Supreme Court ruling, curbing Muslim women's rights to maintenance. This incident reignited debates on UCC and gender justice.

TRIPLE TALAQ MOVEMENT (2017-2019)

Muslim women's rights activists fought against the practice of instant triple talaq, which allowed a Muslim man to divorce his wife simply by saying "talaq" three times. The ShayaraBano case led to a Supreme Court ruling in 2017 that declared triple talaq unconstitutional. Subsequently, the government enacted the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act-2019, criminalizing triple talaq. Despite opposition from conservative elements, this movement strengthened discussions on gender justice and the necessity of a Uniform Civil Code.

THE CONSTITUTIONAL ROOTS OF THE UCC PROPOSAL

Dr. B. R. Ambedkar and other framers of the Indian Constitution envisioned the UCC as a means to ensure equality for all citizens, regardless of religion. This vision is reflected in Article-44 of the Directive Principles of State Policy. However, resistance from religious groups and concerns about cultural diversity made UCC an aspirational goal rather than a mandatory provision. Over the years, the debate over UCC has resurfaced, with proponents advocating for gender equality and legal uniformity, while opponents argue that it could undermine religious freedom.

POTENTIAL IMPACT OF IMPLEMENTING A UNIFORM CIVIL CODE

- Hindu Laws :** The UCC would provide equal rights for women in marriage, inheritance and adoption under the Hindu

- Marriage Act, Hindu Succession Act and Hindu Adoption and Maintenance Act.
- **Muslim Laws :** Sharia-based laws would be replaced, abolishing practices like triple talaq and polygamy while ensuring equal rights for women in divorce, maintenance and inheritance.
 - **Christian & Parsi Laws :** Marriage, divorce and inheritance laws would become uniform across communities, ensuring gender equality.
 - **Special Marriage Act :** A secular marriage framework would be established for all citizens, promoting legal uniformity.
 - **Inheritance & Family Laws :** The UCC would standardize adoption and guardianship laws, ensuring gender parity in inheritance rights.

THE SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF UCC IN GOA AND UTTARAKHAND PROVIDES VALUABLE INSIGHTS. GOA, HAVING INHERITED ITS UCC FROM PORTUGUESE RULE, HAS WITNESSED FEWER LEGAL DISPARITIES BASED ON RELIGION.

WHY HAS INDIA NOT IMPLEMENTED UCC YET?

Despite being a secular country, India has not yet implemented the UCC due to political, religious and cultural concerns. Some argue that personal laws preserve India's rich cultural diversity and should

not be replaced. However, this argument often overshadows the need for gender equality, particularly for women who face discrimination under religious personal laws. Critics believe that UCC is essential for achieving true secularism by ensuring that all citizens are treated equally under the law, irrespective of religion. However, fears of infringing on religious freedoms continue to create hesitation in implementing UCC.

HOW UCC CAN CONTRIBUTE TO A BETTER INDIA

The implementation of a Uniform Civil Code would be a transformative step toward ensuring equality and justice for all citizens. A common set of laws for marriage, divorce, inheritance and adoption would eliminate legal disparities among communities, fostering national unity. UCC would particularly empower women by abolishing discriminatory religious laws.

The successful implementation of UCC in Goa and Uttarakhand provides valuable insights. Goa, having inherited its UCC from Portuguese rule, has witnessed fewer legal disparities based on religion. Similarly, Uttarakhand has begun implementing aspects of UCC in personal laws related to marriage and inheritance, ensuring greater protection for women and marginalized groups. These examples demonstrate that legal uniformity strengthens societal cohesion.

If implemented nationwide, the UCC would eliminate religious-based legal discrimination and create a more inclusive and just society, fulfilling the constitutional promise of equality. The time has come for India to overcome political and religious barriers and ensure that every citizen enjoys equal rights, irrespective of their religious identity. ■

(Author is Associate professor, School of Law Governance and public policy, Chanakya University, Bengaluru)

नए भारत की संभावनाओं पर मंथन

‘भा

रतीय ज्ञान परंपरा, नवाचार और नेतृत्व पर केंद्रित धिंक इंडिया दक्षिणापथ सम्मेलन-2025 का भव्य आयोजन गत 20 एवं 21 सितंबर को चेन्नई में हुआ। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के प्रतिष्ठित टी.टी.जगन्नाथन सभागार में आयोजित सम्मेलन में देशभर के प्रतिष्ठित संस्थानों से आए तीन सौ से अधिक छात्र प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। “प्रतिध्वनि: भारत के लिए नवोन्मष, विश्व के लिए नेतृत्व” विषय पर आधारित दो दिवसीय सम्मेलन विचार, दृष्टि और संकल्प से परिपूर्ण रहा।

सम्मेलन का शुभारंभ तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन.रवि ने दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया। अपने संबोधन में उन्होंने छात्रों से कहा कि वह “उधार लिए गए आख्यानों” से परे जाकर भारत को उसकी मौलिक दृष्टि से समझें। कारण यह है कि भारत की वास्तविक प्रगति तभी संभव हो सकेगी, जब क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर निर्माण जैसे भविष्यवादी क्षेत्रों में स्वदेशी नेतृत्व प्राप्त करेगा। उन्होंने छात्रों को चुनौतियों से नहीं घबराने की सलाह देते हुए कहा कि चुनौतियों को स्वीकार करके ही महान भारत के निर्माण की राह प्रशस्त होगी।

सम्मेलन में आईआईटी, मद्रास के निदेशक प्रा.वी.कामकोटी, अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान, धिंक इंडिया के राष्ट्रीय प्रमुख सुमित पांडेय, संयोजक आकांक्षा वराडे के साथ ही सम्मेलन समन्वयक इंदुचूडन रमेश उपस्थित रहे। सम्मेलन के प्रथम दिन आयोजित सत्रों में भारतीय परंपरा, दर्शन और अर्थनीति पर सार्थक चर्चा हुई। आर्य वैद्य फार्मेसी के प्रबंध निदेशक देवदास वारियर ने आयुर्वेद के 5P मॉडल- Predictive, Preventive, Personalised, Participatory और Precise को आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसी तरह “दक्षिणापथ” की ऐतिहासिक भूमिका की चर्चा करते हुए सेंटर फॉर साउथ इंडियन स्टडीज के निदेशक डा. संदीप कुमार ने बताया कि यह मार्ग सदियों से भारतीय संस्कृति की रक्षा करता आया है। उन्होंने भारत की कहानी भारत के अपने दृष्टिकोण से ही बताए जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। विख्यात अर्थशास्त्री एस.गुरुमूर्ति ने आर्थिक आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा कि जीवनशैली का आयात खतरनाक है, क्योंकि यह मानसिक और सांस्कृतिक रूप से परतंत्र बना देती है। उन्होंने भारतीय मूल्य प्रणाली को “कर्तव्य आधारित” बताते हुए छात्रों से अधिकार के



साथ ही कर्तव्य के विषय में भी गंभीरता से विचार करने के लिए कहा। छात्रों को सम्बोधित करते हुए अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान ने कहा कि भारत के युवाओं में अपार ऊर्जा है, आवश्यकता है केवल उसे राष्ट्रहित में दिशा देने की।

सम्मेलन के दूसरे दिन का आरंभ “न्यायपालिका@2047” विषय पर मद्रास उच्च न्यायालय (मदुरै पीठ) के न्यायमूर्ति जी.आर.स्वामीनाथन के प्रभावी संबोधन से हुआ। उन्होंने कहा कि यदि 2047 तक विकसित भारत बनना है, तो न्याय व्यवस्था को भी समानांतर रूप से विकसित करना होगा। भ्रष्टाचार और प्रक्रिया-जन्य जटिलता इसके बड़े शत्रु हैं। “कार्य का भविष्य” पर आयोजित सत्र में पश्चिमी श्रीधर वैम्बु ने छात्रों से कहा कि उद्यमिता का अर्थ भय पर विजय प्राप्त करना है। एआई से डरने की नहीं, उसे दिशा देने की ज़रूरत है। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि वह तकनीक के उपभोक्ता नहीं, निर्माता बनें। सम्मेलन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने “टाउनहॉल” सत्र में नई शिक्षा नीति-2020 पर संवाद करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति दो अन्य व्यक्तियों को शिक्षित करे, यही असली सामाजिक उत्तरदायित्व है। इस अवसर पर धिंक इंडिया और आईआईटी मद्रास के बीच नवाचार और छात्र-आधारित अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता भी हुआ। सम्मेलन के एक अन्य सत्र में आध्यात्मिक गुरु स्वामी मित्रानंद (चिन्मय मिशन) ने कहा कि भारत प्रारंभ से ही विश्वगुरु रहा है और अब केवल उस आत्मविश्वास को जगाने की आवश्यकता है। सम्मेलन के दौरान छात्र प्रतिभाओं की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने वातावरण को उत्साहपूर्ण बना दिया। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

‘देश की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में हो फार्मेसी विद्यार्थियों का योगदान’

देश के फार्मेसी क्षेत्र में अधिक से अधिक कार्य करते हुए स्वदेशी औषधियों के उत्पादन एवं व्यापार को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि वर्तमान समय में विश्व के कई देश भारत में उत्पादित स्वदेशी दवाओं का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन इस विषय पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसमें फार्मेसी विद्यार्थियों की अहम भूमिका हो सकती है। लक्ष्य यह होना चाहिए कि विश्व के अधिकतर देश भारत में उत्पादित औषधियों का उपयोग करें।

इंदौर स्थित ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल कालेज में आयोजित अभाविप आयाम फार्माविजन के राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेने आए फार्मेसी विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय फार्मासिस्ट विकास के लिए नवाचार और प्रभाव, विकसित भारत @2047 विषय पर आधारित यह आयोजन एक शैक्षणिक कार्यक्रम के साथ ही भविष्य की संभावनाओं, नवाचारों और छात्रों की ऊर्जा का ऐसा संगम बन गया है, जिसने सभी को प्रेरित किया। सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि आयुष मंत्री परमार ने युवाओं से आग्रह किया कि वह नवाचार और समर्पण को अपना मूल मंत्र बनाकर देश को विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचाने में अपना योगदान करे।

सम्मेलन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के राष्ट्रीय महामंत्री डा. वीरेंद्र सोलंकी ने कहा कि आने वाले वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में युवाओं की भूमिका निर्णायक होगी और छात्र अपने विचारों और प्रयोगों से इस क्षेत्र को नई दिशा देंगे। फार्मा रिटेल चेन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन देशपांडे ने मुख्य वक्ता के रूप में अपनी उद्यमशीलता की यात्रा साझा करते हुए बताया कि किस प्रकार उन्होंने नवाचार और साहस के कारण स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में

एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने कहा कि यदि जुनून और लगन हो तो किसी भी सपने को साकार किया जा सकता है।

सम्मेलन के समापन अवसर पर इंदौर के महापौर अधिवक्ता पुष्टमित्र भार्गव और अभाविप के राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री देवदत्त जोशी ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया और उनके प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर अभाविप के महामंत्री डा. वीरेंद्र सिंह सोलंकी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. छगनभाई पटेल, फार्मा विजन के राष्ट्रीय संयोजक अनिकेत सेल्के, अभाविप के क्षेत्रीय संगठन मंत्री चेतस भाई सुखाड़िया, फार्माविजन की प्रांत संयोजिका कामाक्षा गौड़ उपस्थित रहे। सम्मेलन में देशभर से आए आठ सौ से अधिक फार्मेसी छात्र, शिक्षाविद् और उद्योग विशेषज्ञ शामिल हुए। नेपाल के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय रंग दे दिया। सम्मेलन में कई आकर्षक गतिविधियों का आयोजन हुआ, जिनमें पोस्टर प्रस्तुति, मॉडल प्रदर्शन, फार्मा क्विज प्रमुख रहे।

क्या है फार्माविजन

फार्माविजन फार्मेसी छात्रों का एक अखिल भारतीय मंच है, जिसका उद्देश्य छात्रों को पाठ्यपुस्तकों से परे सोचने, सक्रिय भागीदारी करने और सामूहिक रूप से भारत में फार्मेसी शिक्षा, अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार लाने के लिए प्रेरित करना है। “फार्माविजन” भविष्य के फार्मासिस्टों को सशक्त बनाने और उन्हें अपने देशवासियों एवं राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने का कार्य करता है। यह छात्रों में व्यावसायिकता का विकास करता है ताकि वह फार्मासिस्ट बनने के बाद चिकित्सा के विज्ञान, मानवीयता और कला के साथ कार्य करें। ■

(राष्ट्रीय छात्रशिवित टीम)

समग्र स्वास्थ्य सेवा पर चिंतन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) आयाम मेडिविजन का ४वां राष्ट्रीय सम्मेलन महाराष्ट्र स्थित अहिल्यानगर में संपन्न हुआ। डा. विठ्ठलराव विके पाटिल फाउंडेशन के मेडिकल कालेज में हुए सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से तीन से अधिक मेडिकल एवं दंत चिकित्सा के छात्रों ने भाग लिया। सम्मेलन का ध्येय वाक्य “समग्र स्वास्थ्य सेवा: मन, शरीर, जीवनशैली” रखा गया था।

सम्मेलन का शुभारंभ गत 13 सितंबर को दीप प्रज्ज्वलन और वंदे मातरम के गायन के साथ हुआ। उद्घाटन सत्र में महाराष्ट्र के जल संपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, एमयूएजेएस के प्रति-कुलपति मिलिंद निकुंभ, अभाविप के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री एस. बालकृष्ण, मेडिविजन के राष्ट्रीय संयोजक डा. मौलिक ठक्कर और सुप्रिया देशमुख उपस्थित रहे।

इस अवसर पर राष्ट्रीय संयोजक डा. ठक्कर ने मेडिविजन के मिशन एवं एमसीआई के स्थान पर एनएमसी की स्थापना, नीट-पीजी पेपर लीक के विरुद्ध आंदोलन एवं सेवा कार्य जैसे नेत्रकुंभ, सेवा-अनुभूति शिविर और घर-घर कोविड परीक्षण अभियान आदि का उल्लेख करते हुए मेडिविजन के कार्यों की जानकारी सामने रखी। अपने संबोधन में राज्य के जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने अहिल्यानगर की शैक्षणिक संस्कृति और अभाविप की भूमिका को सामने रखा, जबकि प्रति-कुलपति मिलिंद निकुंभ ने युवाओं को “विकसित भारत-2047” के टूटिकोण से जोड़ने का आह्वान किया। सम्मेलन में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री एस. बालकृष्णन ने अभाविप के राष्ट्रीय निर्माण कार्यों एवं भारत की वैश्विक भूमिका पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड काल में किए गए वैश्विक सहयोग का स्मरण किया। रोल मॉडल एवं समग्र चिकित्सा विमर्श पर आयोजित सत्र में 10 रुपए वाले डाक्टर के रूप में प्रसिद्ध डा. नारायण और डा. अभिनंदन बोकरिया के बीच प्रेरणादायक संवाद हुआ। डा. नारायण ने केरल के अद्वापड़ी क्षेत्र में निर्धन जनजातीय समुदायों के लिए

निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा की अपनी यात्रा साझा की, जो स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित रही। समग्र चिकित्सा पर आयोजित सत्र का संचालन डा. सुरेश पाटणकर और डा. मंदार साने ने किया। सत्र में रोबोटिक सर्जरी, 3D बायोप्रिंटिंग, लिवर प्रत्यारोपण, आयुर्वेदिक जीवनशैली चिकित्सा और योग-ध्यान के वैज्ञानिक लाभों पर विचार-विमर्श किया गया।

सम्मेलन के दौरान प्रस्ताविक सत्र में मेडिकल शिक्षा में सुधार और मानसिक स्वास्थ्य पर जोर संबंधित विषय पर दो प्रस्ताव पारित किए गए। प्रस्ताव में नीट-पीजी मूल्यांकन में पारदर्शिता, “वन नेशन, वन स्टाइपेंड” नीति, संविदात्मक नियुक्तियों का अंत, डेंटल सीटों की शुरुआत, क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप दन्त चिकित्सा शिक्षा सीटों में वृद्धि, छात्रों के कल्याण हेतु निर्धारित समय, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान, इंडक्शन कार्यक्रमों में मानसिक स्वास्थ्य का समावेश, कार्य घंटों में सुधार, समेकित स्वास्थ्य सेवा को प्रोत्साहन, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन जैसे विषय को प्रमुखता से उठाया गया है।

सम्मेलन के दूसरे दिन अभाविप के डा. प्रशांत साठे ने अपने व्याख्यान “स्वस्थ मन-समृद्ध भारत की कुंजी” में कहा कि मानसिक रूप से सशक्त व्यक्ति ही सशक्त समाज का निर्माण कर सकता है। प्रतिभागियों ने बाद में जीवनरक्षक कौशल, प्रसूति एवं स्त्रीरोग विज्ञान: सामान्य प्रसव को सामान्य बनाने, इम्प्लांटोलॉजी प्रशिक्षण जैसी विभिन्न कार्यशालाओं में हिस्सा लिया। समापन सत्र में 2025-26 के लिए नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। समापन सत्र में अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री डा. वीरेंद्र सोलंकी, राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री देवदत्त जोशी, मेडिविजन प्रमुख आशीष चंदेल, राष्ट्रीय संयोजक डा. मौलिक ठक्कर उपस्थित रहे। दो दिवसीय सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले प्रतिनिधियों ने संकल्प लिया कि वह अपने-अपने राज्यों और संस्थानों में मेडिविजन के मिशन ‘सेवा, संवेदना और समर्पण’ को और गति प्रदान करेंगे। ■

(राष्ट्रीय छात्रशावित टीम)

छात्राओं को आत्मनिर्भर बना रहा है सर्जना निखार शिविर



अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) दरभंगा द्वारा आयोजित सर्जना निखार शिविर का भव्य समापन गत 10 सितंबर को हुआ। जुबली हॉल में संपन्न समापन समारोह कार्यक्रम का शुभारंभ नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश मिश्रा, अभाविप की राष्ट्रीय मंत्री क्षमा शर्मा, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रा. संजय कुमार चौधरी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री डा. याज्ञवल्क्य शुक्ल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूजा कश्यप, विभाग प्रमुख प्रा. अमृत झा एवं विभाग छात्रा प्रमुख तेजस्विता पांडे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलन कर मां सरस्वती एवं स्वामी विवेकानन्द जी के चित्र पर पुष्ट अर्पित कर किया।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूजा कश्यप ने प्रस्तावना प्रस्तुत करते हुए बताया कि सर्जना निखार शिविर का आयोजन छात्राओं की प्रतिभा को निखारकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य कर रहा है। इस वर्ष भी शिविर का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि जीवेश मिश्रा ने कहा कि कौशल विकास आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है और अभाविप

दरभंगा द्वारा चलाया जा रहा यह शिविर उत्तर बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे कार्यक्रमों का विस्तार अन्य जिलों में भी होना चाहिए। कुलपति प्रा. संजय कुमार चौधरी ने शिविर को स्वरोजगार और स्वावलंबन का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। क्षेत्रीय संगठन मंत्री डा. याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि मिथिला की परंपरा में शक्ति की उपासना होती रही है और सर्जना निखार शिविर उसी परंपरा का जीवंत प्रतीक है। मुख्य वक्ता क्षमा शर्मा के अनुसार यह शिविर छात्राओं के भीतर छुपी हुई प्रतिभा को सामने लाकर उन्हें समाज में अपनी पहचान बनाने का अवसर देता है। उन्होंने छात्राओं को संदेश दिया कि सोशल मीडिया की आभासी दुनिया से निकलकर वास्तविक जीवन में कदम रखना ही सफलता की कुंजी है। विभाग प्रमुख प्रा. अमृत झा ने बताया कि शिविर से प्रशिक्षित होकर अनेक छात्राएं आज अपने कौशल के बल पर स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर हैं।

समारोह में योगा प्रशिक्षक अनू कुमारी, कंप्यूटर प्रशिक्षक राहुल कुमार सिंह और विपिन कुमार, व्यक्तित्व

विकास प्रशिक्षक सत्येंद्र झा एवं आर. एन. चौरसिया, पत्रकारिता प्रशिक्षक संतोष दत्त झा, नृत्य प्रशिक्षक रवि सिंह, संगीत प्रशिक्षक हिमांशु झा और सोन दास, स्पोकेन इंग्लिश प्रशिक्षक राजा झा, मिथिला पॉटिंग प्रशिक्षक दर्शन कुमार, मेहंदी प्रशिक्षिका रिकी शर्मा, फाइन आर्ट प्रशिक्षिका आकांक्षा झा और कविता कुमारी, सिलाई प्रशिक्षिका निक्की कुमारी, ब्यूटीशियन प्रशिक्षिका रितु कुमारी और ईशा कुमारी को सम्मानित भी किया गया।

क्या है सर्जना निखार शिविर

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की दरभंगा इकाई द्वारा प्रत्येक वर्ष सर्जना निखार शिविर आयोजित किया

जाता है। 2006 से प्रत्येक वर्ष गर्भियों की छुट्टियों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य छात्राओं में कौशल विकास, आत्मनिर्भरता और व्यक्तित्व निर्माण को बढ़ावा देना है। शिविर के दौरान एक माह तक सोलह कलाओं में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। छात्राएं एक विषय में पंजीयन कर अपने समय के अनुसार एक से अधिक विषयों का भी निःशुल्क प्रशिक्षण ले सकती हैं। शिविर में कंप्यूटर, अंग्रेजी भाषा, डिजिटल मार्केटिंग, सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, फाइन आर्ट, मेहंदी, ब्यूटीशियन जैसे व्यावसायिक कोर्स की जानकारी प्रदान की जाती है। ■

(राष्ट्रीय छात्रशिविर टीम)

| शिक्षा |

देश में आरंभ हुए पांच डिजिटल विश्वविद्यालय

भारत में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना करने का सपना साकार हो गया है। देश में पांच डिजिटल विश्वविद्यालय का आरंभ होने से उच्च-गुणवत्ता वाली डिजिटल शिक्षा अधिक से अधिक युवाओं को मिल सकेगी। मुजफ्फरपुर (बिहार), बालासोर (ओडिशा), तिरुपति (आंध्र प्रदेश), लुंगलेर्ह (मिजोरम) और दादरा-नागर हवेली तथा दमन-दीव (डीएनएचडीडी) में आरम्भ हुए डिजिटल विश्वविद्यालय का वर्चुअल उद्घाटन गत 2 अक्टूबर को केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया।

नाइलिट डिजिटल विश्वविद्यालय (एनडीयू) प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आरंभ हुए डिजिटल विश्वविद्यालय के माध्यम से उच्च-गुणवत्ता वाली डिजिटल शिक्षा तक अधिक से अधिक लोगों की पहुंच बनाई जाएगी। नाइलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म एआई, साइबर सुरक्षा, डाटा साइंस, सेमीकंडक्टर सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों में उद्योग-केन्द्रित कार्यक्रम प्रदान करेगा। साथ ही युवाओं को भविष्य के लिए तैयार कौशल से लैस करने के लिए

लचीले डिजिटल शिक्षण मोड और वर्चुअल लैब प्रदान करेगा।

नाइलिट डिजिटल विश्वविद्यालय प्लेटफॉर्म (एनडीयू. डिजिटल) को विश्वस्तरीय, समावेशी, किफायती और रोज़गार-उन्मुख डिजिटल शिक्षण इकोसिस्टम बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य उच्च-गुणवत्ता वाली डिजिटल शिक्षा तक अधिक से अधिक लोगों की पहुंच बनाना, डिजिटल इंडिया, एनईपी-2020 और स्किल इंडिया के लक्ष्यों का समर्थन करने के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उभरती तकनीकों में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कार्यबल तैयार करना है। प्लेटफॉर्म का लक्ष्य 2030 तक 40 लाख शिक्षार्थियों को लक्षित करते हुए पूरे भारत में शिक्षार्थियों को सशक्त बनाना है। विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए 101 कोर्स रखे गए हैं। अलग-अलग कोर्स के लिए फीस भी अलग-अलग होगी। नाइलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर छात्र कोर्स एवं फीस की पूरी जानकारी ले सकते हैं। ■

(राष्ट्रीय छात्रशिविर टीम)

देश के 54 निजी विश्वविद्यालय डिफॉल्टर घोषित

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नियमों के अनुपालन में डिलाई करने के कारण देश के 54 निजी विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। यूजीसी ने यह कार्यवाई यूजीसी अधिनियम-1956 की धारा-13 के तहत अनिवार्य जानकारी प्रस्तुत नहीं करने एवं अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक जानकारी नहीं देने के कारण की है। डिफॉल्टर घोषित किए गए निजी विश्वविद्यालयों में मध्य प्रदेश के सर्वाधिक दस विश्वविद्यालय, गुजरात के आठ, सिक्किम के पांच और उत्तराखण्ड के चार विश्वविद्यालय शामिल हैं। गत 24 सितंबर को डिफॉल्टर विश्वविद्यालयों की सूची जारी करने के साथ ही यूजीसी ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने की चेतावनी भी दी है। यूजीसी का कहना है कि जो गाइडलाइन बनाई



गई हैं, वह विश्वविद्यालयों में होने वाली पढ़ाई और पाठ्यक्रम को लेकर पारदर्शिता बढ़ाती है। डिफॉल्टर घोषित किए विश्वविद्यालयों को नियमों के क्रियान्वयन के लिए कई बार नोटिस जारी करने के साथ पत्र के माध्यम से सूचित किया गया। लेकिन कोई उत्तर न मिलने की स्थिति में यह कार्यवाई की गई है। डिफॉल्टर घोषित किए गए 54 विश्वविद्यालयों में गुजरात, हरियाणा, असम, पंजाब, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखण्ड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं। विश्वविद्यालयों के नाम यूजीसी वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। ■

(राष्ट्रीय छात्रावित टीम)

| दिल्ली |

राष्ट्रनीति पाठ्यक्रम से छात्र जानेंगे संघ एवं स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान

देश की राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) एवं स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान की शिक्षा देने के लिए शिक्षा विभाग ने राष्ट्रनीति नामक पाठ्यक्रम आरंभ किया है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत छात्रों को न केवल संघ के आरंभ होने की परिस्थितियों और विचारधारा की जानकारी दी जाएगी, साथ ही स्वाधीनता संघर्ष से लेकर विभिन्न संकटकाल में संघ स्वयंसेवकों की उल्लेखनीय भूमिका से भी अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक जागरूकता, अनुशासन, सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व पर संघ

की भूमिका को रेखांकित किया जाएगा। पाठ्यक्रम के तहत छात्रों को संघ के गठन और इतिहास, विचारधारा और संघ स्वयंसेवकों की भूमिका की विस्तृत जानकारी मिल सकेगी। पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में सामाजिक चेतना और नागरिक कर्तव्यों की समझ विकसित करना है। जानकारी के अनुसार राष्ट्रनीति पाठ्यक्रम में वीर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार वल्लभभाई पटेल और नेताजी सुभाषचंद्र बोस जैसे नेताओं पर भी विशेष अध्याय को शामिल किया गया है। नए अध्याय की शिक्षा देने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण जारी है। ■

(राष्ट्रीय छात्रावित टीम)

अभाविप के संस्थापक सदस्य एवं शिक्षाविद प्रा. वी. के. मल्होत्रा का निधन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के संस्थापक सदस्य, शिक्षाविद, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रा. विजय कुमार मल्होत्रा का गत 30 सितंबर को निधन हो गया। उनकी आयु 93 वर्ष थी। स्वतंत्रता के बाद देश में युवा चेतना को संगठित करने और राष्ट्रीय विचारधारा पर आधारित छात्र आंदोलन को दिशा देने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह पांच बार संसद सदस्य एवं दो बार विधायक भी रहे।

अभाविप की स्थापना के आरंभिक काल में उन्होंने न केवल संगठन की वैचारिक नींव को मजबूत किया, बल्कि देशभर के विश्वविद्यालयों में राष्ट्रवादी शिक्षा, अनुशासन और चरित्र निर्माण के संदेश को फैलाने में अहम योगदान दिया। उनका जीवन उन सभी विद्यार्थियों और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो राष्ट्र निर्माण के पथ पर शिक्षा और संगठन दोनों को समान रूप से महत्व देते हैं।

उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए अभाविप ने कहा कि प्रा. मल्होत्रा जी का जीवन, विचार और कार्य आज भी अभाविप के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने अपने समर्पण, संगठन कौशल और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से युवाओं को भारत की एकता एवं प्रगति के लिए कार्य करने का संदेश दिया। राष्ट्रीय राजधानी को शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाने में उनका प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने विवेकानंद कालेज, दीनदयाल उपाध्याय कालेज, राजधानी कालेज सहित लगभग पंद्रह कालेजों की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। स्कूलों की संख्या बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के साथ ही उन्होंने खेल के महत्व को समझा और दिल्ली में भारत केसरी दंगल आरंभ कराया। उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई अन्य नेताओं ने उन्हें अभाविप एवं भाजपा का मजबूत स्तंभ बताया और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी।

जानकारी के अनुसार प्रा. मल्होत्रा का जन्म 3 दिसंबर 1931 को लाहौर में हुआ था। तत्कालीन समय में लाहौर भारत के पंजाब प्रांत का हिस्सा था। वह 1972 से 1975 तक दिल्ली प्रदेश जनसंघ के अध्यक्ष रहे। 1977 से 1980 तथा 1980 से 1984 तक दो बार भारतीय जनता पार्टी, (दिल्ली प्रदेश) के अध्यक्ष चुने गए। वह 1967 में मुख्य कार्यकारी पार्षद निर्वाचित हुए थे। 2004 के चुनाव में दिल्ली भाजपा के वह एक मात्र ऐसे नेता थे, जिन्हें दिल्ली में लोकसभा चुनाव में विजय हासिल हुई थी। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

सुधी पाठकों !

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' अक्टूबर-2025 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है। यह अंक महत्वपूर्ण लेख एवं विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों एवं खबरों को समाहित किए हुए हैं। आशा है, यह अंक आपके आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा। कृपया 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव एवं विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई-मेल पर अवश्य भेजें : -

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति'

26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,

नई दिल्ली-110002

फोन : 011-23216298

www.chhatrashakti.in

 rashtriyachhatrashakti.abvp@gmail.com

 www.facebook.com/Rchhatrashakti

 www.twitter.com/Rchhatrashakti

 www.instagram.com/Rchhatrashakti

...नहीं रहे अभाविप के पूर्व क्षेत्रीय संगठन मंत्री राधेश्याम जी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के पूर्व क्षेत्रीय संगठन मंत्री राधेश्याम जी का गत 28 सितंबर को निधन हो गया। 85 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन पर संघ एवं अभाविप ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनका निधन एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने संगठन को जीवन का ध्येय बनाकर अनेकों कार्यकर्ताओं को तैयार किया और राष्ट्रसेवा का पथ दिखाया।

पिछले सात दशक से संघ परिवार से जुड़े रहे राष्ट्रीय राधेश्याम जीवनभर राष्ट्र सेवा में समर्पित रहे। उनका अंतिम संस्कार 29 सितंबर को हाथरस में हुआ। उनकी अंतिम यात्रा हाथरस स्थित पैतृक आवास से निकली, जिसमें हजारों स्वयंसेवक और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। रा.स्व संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले एवं अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख रामलाल भी अंतिम यात्रा में सम्मिलित हुए और पार्थिव शरीर पर अभाविप का झंडा एवं शॉल ओढ़ाकर पुष्टांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार में अभाविप के प्रांत

अध्यक्ष डा. सौरभ सेंगर सहित बड़ी संख्या में अभाविप कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय राधेश्याम जी का जन्म 4 अगस्त 1949 को हाथरस में हुआ था। वह 1961 में स्वयंसेवक के रूप में संघ सेवा कार्यों में सक्रिय हुए और प्रारंभिक शिक्षा के बाद 1972 में प्रचारक जीवन का संकल्प लिया। उन्होंने अलीगढ़, बरेली, आगरा, ब्रज प्रांत के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में संगठन के कार्य का दायित्व संभाला। 1984 में उन्हें अभाविप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संगठन मंत्री तथा 1989 में उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री का दायित्व सौंपा गया। उनके नेतृत्व में अभाविप के कार्यों का काफी विस्तार हुआ और अनेक पूर्णकालिक कार्यकर्ता तैयार हुए। वह वर्तमान में रा.स्व. संघ में ब्रज प्रांत, बरेली, मेरठ, आगरा और उत्तराखण्ड के क्षेत्रीय छात्रावास प्रमुख का दायित्व निर्वहन कर रहे थे। उन्होंने अनेक पुस्तकों का संकलन एवं लेखन भी किया। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण संगठन, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहा। ■

(राष्ट्रीय छात्रावित टीम)

उपलब्धि |

आईआईएम-अहमदाबाद का पहला विदेशी परिसर दुर्बई में

भारत के प्रमुख व्यावसायिक स्कूल भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम-अहमदाबाद) ने अपना पहला विदेशी परिसर दुर्बई में स्थापित किया है। परिसर का उद्घाटन दुर्बई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने किया। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, संयुक्त अरब अमीरात के कार्यवाहक उच्च शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री डा. अब्दुल रहमान अब्दुल मन्नान अल अवार और आईआईएमए के निदेशक प्राध्यापक भरत भास्कर सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रधान ने कहा कि दुर्बई में आईआईएम

दुर्बई परिसर का उद्घाटन होना भारतीय शिक्षा के वैश्वीकरण की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि है। आईआईएम का यह परिसर भारत की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा को विश्व तक पहुंचाएगा। गत 11 सितंबर को आयोजित उद्घाटन समारोह में श्री प्रधान ने दुर्बई में भारतीय शिक्षण संस्थानों द्वारा किए गए योगदान, विशेष रूप से पारस्परिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने, वैश्विक संपर्क को बढ़ावा देने एवं संयुक्त अरब अमीरात में और अधिक उच्च-गुणवत्ता वाले भारतीय संस्थानों की स्थापना के लिए दिए गए समर्थन की सराहना के लिए डा. अब्दुलरहमान अल अवार का धन्यवाद किया। ■

(राष्ट्रीय छात्रावित टीम)

भावभीनी श्रद्धांजलि



याधेन्याम जी

(4 अगस्त 1949-28 सितंबर 2025)

भावभीनी श्रद्धांजलि



प्रा. वी. के. महोत्रा

(3 दिसंबर 1931-30 सितंबर 2025)